Concern over the acute power crisis in Uttar Pradesh

श्री अमीर आलम खान (उत्तर प्रदेश) : उपसभाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से सरकार का ध्यान उत्तर प्रदेश में मौजूदा बिजली के संकट की ओर आकर्षित करना चाहता हूं। जैसा कि सभी जानते हैं कि उत्तर प्रदेश बिजली के संकट से जूझ रहा है तथा विगत माह से यह संकट भयंकर रूप धारण कर चुका है। इसके परिणामस्वरूप पूरे प्रदेश में हाहाकार मचा हुआ है।

गाज़ियाबाद, मेरठ, मुजफ्फरनगर, मुरादाबाद, वाराणसी, कानपुर तथा इलाहाबाद आदि जैसे महत्वपूर्ण नगरों में 10-12 घंटे तक की बिजली कटौती एक सामान्य बात हो गई है। इसके कारण किसान, व्यापारी, विद्यार्थी एवं अन्य सभी वर्गों का जीना दूभर हो गया है। इस भीषण गर्मी में बिजली की कटौती से छोटे-छोटे बच्चे विभिन्न प्रकार के रोगों से पीड़ित हो रहे हैं। बिजली न होने से, पानी का संकट पैदा हो गया है, खेत सूखे पड़े हैं। उद्योग-धंधे बंद होने के कगार पर हैं। सामान्य जन-जीवन बुरी तरह प्रभावित हो रहा है। बिजली की निर्बाध आपूर्ति हेतु लोग अनशन, धरना, प्रदर्शन आदि करने को मजबूर हैं। राज्य सरकार सारा दोष केन्द्र सरकार पर मढ़ रही है कि केन्द्र से समुचित मदद नहीं मिल रही है और एन.टी.पी.सी. की राज्य में विभिन्न इकाइयों ने बिजली देने से मना कर दिया है, जिससे प्रदेश बिजली खरीदने पर मजबूर है।

मैं केन्द्र सरकार से निवेदन करूंगा कि सरकार उत्तर प्रदेश को बिजली के गंभीर संकट से राहत प्रदान करे, जिससे कि इस समस्या से लोगों को राहत मिल सके, अन्यथा उत्तर प्रदेश अति पिछड़े प्रदेशों की गिनती में शुमार होने लगेगा। धन्यवाद।

Demand to restore the rights and privilages of Indian fishermen

SHRI TIRUCHI SIVA (Tamil Nadu): Sir, the Government of India and the Government of Sri Lanka signed an agreement on 26.06.1974 with a view to determining the boundary line between the two countries in the waters between Adam's Bridge and Palk Strait. According to article 5 and 6 of the agreement, the traditional rights of Indian fishermen, including the right to fish near Katchatheevu were accepted and conceded. In fact, article 6 of the agreement stipulated categorically that "the vessels of India and Sri Lanka will enjoy in each others' waters such rights as they have traditionally enjoyed therein".

A second agreement was signed on 23.3.1976 for demarcating the boundary between the two countries in the Gulf of Mannar. This agreement sought only to define the boundary line in the area not covered by the earlier agreement. All the provisions of 1974 agreement remain valid and have not been superseded. It was also stated that Indian fishermen could dry their nets in Katchatheevu. But, time and again, our fishermen have been arrested, attacked and shot dead in these waters. The arrests as well as the arbitrary shooting incidents of the innocent fishermen have continued unabated, terrorizing the Indian fishermen, and, causing deep anguish to every citizen of the State.

In view of the serious nature of the issue, the Sri Lankan Government may be told in clear terms about the legitimate rights of India in this issue and the rights and privileges of the Indian fishermen of fishing in these waters must be restored. Thank you.